Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
www.researchguru.net
Volume-14, Issue-1, June-2020

भारत एवं पाकिस्तान की विभाजनकारी विचारधारा का पाकिस्तानी उर्दू अखबारों में प्रभाव

डॉ. मनोज कुमार पटेल
गांव: उमेदपुर पोस्ट: दधालिया तहसील: मोडासा जिला: अरवल्ली गुजरात भारत
patelmanoj333@gmail.com Mob: 9662149985

१. प्रस्तावना

पाकिस्तानी उर्दू अखबारों में विभाजनकारी विचारधारा का प्रभाव देखने से पूर्व भारत और पाकिस्तान के बीच उसका उद्भव एवं विकास कैसे हुआ? उसका विवरण दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजनकारी विचारधारा के पनपने के पीछे अंग्रेजों की "फूट डालो और राज करो" की नीति, बृहद भारत का विभाजन, दोनों राष्ट्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा, हिंदूओं और मुस्लिमों के बीच हुए धार्मिक दंगे, दोनों राष्ट्रों से लोगों का स्थानांतरण एवं उससे पैदा हुई शरणार्थियों की समस्या, जम्मू-कश्मीर समस्या और उसको लेकर दोनों राष्ट्रों के बीच १९४७ में हुआ पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध इत्यादि घटनाएं कारण रूप है। उसके बाद इस विचारधारा को मजबूत करने में १९६५ एवं १९७१ का भारत पाकिस्तान युद्ध, पंजाब समस्या, १९८० के दशक में हुआ सियाचिन संघर्ष, १९८९ में जम्मू-कश्मीर में हुआ विद्रोह एवं मुजाहिद्दीन त्रासवाद का आरंभ, १९९८ में भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, १९९९ में कारगिल युद्ध, २००१ में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही समझौता एक्सप्रेस में २००७ में बम विस्फोट, २००८ में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर हमला, २०१६ में भारत अधिकृत जम्मू-कश्मीर में पठानकोट पर त्रासवादी हमला, सितंबर २०१६ में भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में भारत के सैन्य ठिकाने पर आतंकवादी हमला एवं आगे चलकर संघर्ष विराम उल्लंघन और भारतीय सुरक्षाबलों पर और अधिक उग्रवादी हमले एवं नियंत्रण रेखा के पार एक सैन्य टकराव, २०१६ के बाद से जारी टकराव में आतंकवादी हमले और दोनों तरफ से राष्ट्रवादी बयान बाजी में वृद्धि, २०१९ में पुलवामा में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर त्रासवादियों द्वारा जानलेवा हमला एवं उसके प्रतिकार के रूप में १९९३ में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया हुआ "खास पसंदीदा राष्ट्र" (Most favoured nation) का सम्मान रद्द कर देना एवं कस्टम ड्यूटी बढ़ाना, अगस्त २०१९ में भारत की संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी देना इत्यादि एवं आए दिन जम्मू-कश्मीर में त्रासवादी वारदातें एवं दोनों राष्ट्रों की सेनाओं के बीच होती रहती गोलाबारी जिम्मेदार है। उनका वर्णन निम्नानुसार है:

२.१ विभाजनकारी विचारधारा का उद्भव एवं विकास

१९४७ एवं १९४८ में भारतीय उप महाद्वीप को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और चार नए स्वतंत्र राष्ट्र बने: भारत, सीलोन (अब श्रीलंका), बर्मा (अब म्यांमार) और पाकिस्तान (जिसमें पूर्व पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) शामिल है) (विकीपीडिया)।

भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार "भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७" के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया था कि, १५ अगस्त १९४७ को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो

अधीराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रितानी सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही १४ अगस्त को संप्रभु पाकिस्तान (बाद में इस्लामी जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और १५ अगस्त को भारतीय यूनियन (बाद में भारत गणराज्य) की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह १९७१ में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है (नेपाल और भूटान इस दौरान भी स्वतंत्र राज्य थे और इस बटवारे से प्रभावित नहीं हुए) (विकिपीडिया)।

१५ अगस्त १९४७ की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में १४ अगस्त को कराची में की गई, ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस १४ अगस्त और भारत में १५ अगस्त को मनाया जाता है (विकिपीडिया)।

भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब पांच लाख लोग मारे गए और करीब १.४५ करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली (विकिपीडिया)।

२.१.१ भारत और पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि

भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में “फूट डालो और राज करो” की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग-अलग समूह में बांट कर रखा। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी, तो कुछ मुसलमानों के प्रति। २०वी सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। भारत में जब आजादी की भावना उभरने लगी तो आजादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदाय के नेताओं में होड रहने लगी (विकिपीडिया)।

सन १९०६ में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर “मुस्लिम लीग” की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि, मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस” हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। “मुस्लिम लीग” ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग मांगे रखी। १९३० में “मुस्लिम लीग” के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मुहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। १९३५ मैं सिंध प्रांत की विधानसभा ने भी यह मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिंदु-मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे। लाहौर में १९४० के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर यह कहा कि वह दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं “हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग है।........... एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में, ऐसे दो राष्ट्रों को साथ बांधकर रखने से असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर रहेगा” (विकीपीडिया)।

हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद है। १९३७ में इलाहाबाद में "हिंदू महासभा" के एक भाषण में वीर सावरकर ने कहा था- आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहां पर दो राष्ट्र है-हिंदू और मुसलमान। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया: "मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृति है ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान है।" बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस छोड़कर न जाए और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गरम दलों के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए (विकिपीडिया)।

अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दीया। "मुस्लिम लीग" ने अगस्त १९४६ में "सीधी कार्यवाही दिवस" मनाया और कोलकाता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब ५००० लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वह विभाजन को स्वीकार करें, ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए (विकिपीडिया)।

२.१.२ भारत के विभाजन की प्रक्रिया

भारत के विभाजन के ढांचे को "३ जून प्लान" या "माउंटबेटन योजना" का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। १८ जुलाई, १९४७ को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता कानून-इंडियन इंडिपेंडेंटस एक्ट पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके के राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन ५६५ राज्यों को आजादी दी गई कि वे चुने कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे? अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफी विवाद हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली (विकिपीडिया)।

२.१.३ भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारा

ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बाटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी। गांधीजी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि, वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजें। जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू किया कर दिया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया (विकीपीडिया)।

२.१.४ भारत और पाकिस्तान में दंगा फसाद

बहुत से विद्वानों का मत है कि, ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला। क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि, बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि, दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध

से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं था। फल स्वरूप दंगे फसाद हुए और बहुत से लोगों की जानें गई और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जाता है कि, इस दौरान लगभग ५ लाख से ३० लाख लोग मारे गए, कुछ दंगों में, तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से (विकिपीडिया)।

२.१.५ लोगों का स्थानांतरण

विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बलात बेघर कर दिया गया। लेकिन भारत में गांधीजी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकते हैं। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग १.४५ करोड लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। १९५१ की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद ७२,२६,००० मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और ७२,४९,००० हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से ७८ प्रतिशत स्थानांतरण पश्चिम में, मुख्य तया पंजाब में हुआ (विकिपीडिया)।

२.१.६ भारत और पाकिस्तान में शरणार्थी

भारत में आए शरणार्थी पश्चिम में मुख्यतः पंजाब और दिल्ली में और पूर्व में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बसाए गए, सिंध से आए शरणार्थी गुजरात और राजस्थान में बसे। पंजाबी बोलने वाले मुस्लिम मुख्यतः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसे और जल्दी ही वहां सम्मिलित हो गए। लेकिन उर्दू बोलने वाले मुस्लिम जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और अन्य प्रांतों से पाकिस्तान गए उन्हें वहां बसने और सम्मिलित होने में बहुत कठिनाइयां आई। इन शरणार्थियों को “मुजाहिर” का नाम दिया गया (विकिपीडिया)।

२.१.७ विभाजन एवं विवाद

१९४७ में भारत गणराज्य एवं स्वतंत्र पाकिस्तान ऐसे दो नए स्वतंत्र राष्ट्रों के उदय के साथ ही भारत से ब्रिटिश प्रशासन का अंत हो गया। “भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७” प्रभाव में आते ही भारत से अंग्रेज प्रशासन समाप्त हो गया और इसके साथ दूसरे समझौते एवं संधियां भी खत्म हो गई थी। अधिनियम में किए गए प्रबंधों के अनुसार रियासतें भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती है या फिर स्वतंत्र रह सकती है। इस वक्त मुस्लिम बहुलता वाले जम्मू-कश्मीर राज्य में हिंदू महाराजा हरि सिंह का शासन चलता था। विभाजन को देखते हुए पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। दूसरी और महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को स्वतंत्र बनाए रखने को लेकर सोच विचार में ज्यादा वक्त लगा दिया (विकिपीडिया)।

ऐसे में इस सूबे के पश्चिमी सरहदी विस्तार में बसे पख़्तून आदिवासियों ने विद्रोह किया। उसको नियंत्रित करने के लिए २५ अक्तूबर १९४७ में महाराजा हरि सिंह ने भारत गणराज्य के साथ समझौता किया। इस समझौते का संकेत था कि, उभय रूप से भारत और पाकिस्तान का जम्मू-कश्मीर राज्य में हस्तक्षेप करना। वैसे भी पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को अपने समाज का हिस्सा मानता था। दूसरी ओर भारत ने राजा हरि सिंह के साथ किए गए समझौते के अनुसार जम्मू-कश्मीर में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु हस्तक्षेप की तैयारियां शुरू कर दी (विकीपीडिया)।

२.१.८ भारत पाकिस्तान युद्ध: १९४७

भारत द्वारा कश्मीर के महाराजा को मदद का वचन दिए जाने पर मुस्लिम त्रासवादी और पाकिस्तानी आदिवासियों ने जम्मू-कश्मीर के बारामुला क्षेत्र में लड़ाई के लिए पहले से ही अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। स्थिति को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप न करने की संधि होने के बावजूद महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार को हस्तक्षेप

करने के लिए कहा। दूसरी और जम्मू-कश्मीर में विद्रोहियों ने प्रवेश कर लिया था। इसमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले थे कि, जो ये सिद्ध कर सके की इस लड़ाई में पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इस वक्त पाकिस्तानी आदिवासी श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में आ पहुंचे थे, जिसको लेकर महाराजा हरि सिंह को तत्काल सैन्य सहयोग की जरूरत थी। आदिवासी और आगे बढ़े इससे पहले भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच सैन्य सहयोग के लिए महाराजा एवं बर्मा के गवर्नर माउंटबेटन के बीच समझौता हुआ। इस कार्य में जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस के स्वयं सेवकों ने भी भारतीय सैन्य को सहयोग किया (विकिपीडिया)।

पहले कश्मीर युद्ध के अंत का परिणाम यह आया कि, १९४८ में भारत ने इस समस्या को सुलझाने के लिए उसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में रखा। शेख अब्दुल्ला इसके विरुद्ध थे। वह जम्मू-कश्मीर की मुक्ति भारतीय सेना के जरिए करवाना चाहते थे। सुरक्षा परिषद ने २१ अप्रैल, १९४८ में ४७ वा प्रस्ताव पारित करके “यूनाइटेड नेशन्स कमिशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान” की रचना की। कमीशन ने तत्काल प्रभाव से युद्ध को बंद करवा दिया। पाकिस्तान एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच समाधान करवाया और विद्रोहियों, पाकिस्तानी एवं भारतीय सैनिकों को वहां से पीछे हट जाने के लिए कहा, लेकिन वहां से कोई नहीं हटा। कमीशन ने मतदान के जरिए जम्मू-कश्मीर की जनता किसके साथ जाना चाहती है? यह तय करने को कहा। लेकिन दोनों राष्ट्रों ने इस सुझाव का अस्वीकार किया। दोनों राष्ट्रों की सेना आज भी वहां आमने-सामने है। स्वतंत्र कश्मीरी सेना भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकी (विकिपीडिया)।

नवंबर, १९४८ में दोनों राष्ट्रों की सरकारें मतदान कराने के लिए तैयार हो गई, लेकिन पाकिस्तान अपना सैन्य वहां से हटाने के लिए नहीं माना। इसलिए भारत ने भी अपने रुख में बदलाव लाते हुए मतदान कराने की बात को नकार दिया। भारत ने पहले पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी सेना हटा लेने को कहा और बाद में मतदान करवाने की बात की। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का अस्वीकार करते हुए कहा कि, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं शेख अब्दुल्ला की मैत्री एवं जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना की उपस्थिति मुक्त मतदान कैसे करने देगी? हां! पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्देशन में अपने सैन्य की वापसी एवं मतदान कराने की दरखास्त रखी थी, जिसका भारत ने अस्वीकार किया था। इसका नतीजा यह निकला कि, पाकिस्तान ने किसी भी प्रस्ताव को नहीं माना। कुछ सालों बाद ४७ वे प्रस्ताव में बदलाव करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोनों राष्ट्रों को नजर में रखते हुए चार नए समझोते तैयार किए। जिसमें जम्मू-कश्मीर से सैन्य को वापस बुलाने के लिए कहा गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने दूसरी ११ दरखास्त तैयार की, जिसका पाकिस्तान ने स्वीकार किया और भारत ने अस्वीकार। बाद में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रकरण ६ अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि, ऐसे कोई हुक्म न किया जाए जो कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रकरण ७ के विरोधी हो (विकीपीडिया)।

२.१.९ भारत-पाकिस्तान युद्धः १९६५ एवं १९७१

१९६५ एवं १९७१ में भारत और पाकिस्तान के बीच दो युद्ध हुए थे। दोनों युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। १९७१ के युद्ध में पाकिस्तान के घोर पराजय के बाद स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने शरणागति दी थी। १९७२ में “शिमला समझौता” हुआ, जो कि संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के मुताबिक था। उसमें यह तय किया गया था कि, दोनों राष्ट्र सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाएंगे (विकिपीडिया)।

२.१.१० जम्मू-कश्मीर विद्रोह एवं त्रासवाद: १९८९

जम्मू-कश्मीर में भारत से आजादी के लिए १९८९ में बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ था। १९८७ में हुए विधानसभा चुनाव में कुछ नतीजे विवादित रहे थे, उसके फलस्वरूप त्रासवादी संगठनों का आविर्भाव हुआ एवं मुजाहिद्दीन त्रासवाद भी पैदा हुआ, जो कि आज तक जारी है। कश्मीर में बड़े पैमाने पर त्रासवाद का आरंभ अफगान मुजाहिद्दीनो ने किया था, जो कि सोवियत-अफगान युद्ध के बाद कश्मीर में आए थे। "जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट" के प्रमुख एवं कश्मीरी यासीन मलिक ने कश्मीर में त्रासवाद को संचालित किया था। उनको अपने इस कार्य में अशफाक माजिद वानी एवं फारूक अहमद दार ने सहयोग दिया था। यासीन मलिक ने पुनः १९९५ में फिर से हिंसा के जरिए एवं मजबूत शांतिपूर्ण प्रयत्नों के जरिए इस समस्या का समाधान करने का आह्वान किया था। मलिक का काम करने का तरीका अपने वरिष्ठ नेताओं से बिल्कुल अलग था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को स्वतंत्र करने की मांग की थी एवं भारत के प्रधानमंत्री के साथ की हुई संधि रद्द कर दी थी। इसका नतीजा यह निकला कि दूसरे अलगाववादी नेता जैसे कि बिट्टा कराटे, सलीम नानाजी एवं अन्य वरिष्ठ नेता फारुक सिद्दीकी से जा मिले। इस त्रासवादी विद्रोह के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि, जम्मू-कश्मीर के त्रासवादी वहां के नागरिक ही है, जिनका उद्भव स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, भारत का विरोध करने के लिए हुआ है। जबकि भारत का कहना था कि, मुस्लिम त्रासवादी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर एवं अफगानिस्तान से आते हैं। उनका उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। भारत का पहले से यह कहना है कि, पाकिस्तान त्रासवादियों को असला-बारूद एवं तालीम देता है। भारत का कहना है कि, त्रासवादी जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की हत्या करते हैं और आरोप भारतीय सेना पर लगाते हैं (विकिपीडिया)।

पाकिस्तान सरकार जम्मू-कश्मीर के त्रासवादियों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बताती है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि, वह सिर्फ उनको नैतिक एवं राजनीतिक मदद करती है। जिसे भारत त्रासवादियों को मदद करना कहता है। पहली बार २००८ में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रमुख आसिफ अली जरदारी ने कश्मीरी अलगाववादियों को "वॉल स्ट्रीट जर्नल" को दि हुई एक भेंटवार्ता में "त्रासवादी" कहा था। इस विधान से कई कश्मीरियों को ठेस पहुंची थी। तूफान, हंगामा हो गया था। भारतीय सेना के पुतले जलाए गए थे (विकिपीडिया)।

२.१.११ कारगिल संघर्ष, १९९९

१९९९ के मध्य में त्रासवादी एवं पाकिस्तानी सेना के जवानों ने मिलकर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर पर हमला किया। सर्दियों के मौसम में भारतीय सेना नियमित रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा से वापस आ जाती थी। यहां का मौसम सर्दियों के दिनों में इतना प्रतिकूल होता है कि सेना का नियंत्रण रेखा पर डटे रहना मुश्किल हो जाता है। इस भौगोलिक मुश्किल का लाभ उठाकर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के त्रासवादियो ने कारगिल में घुसकर कारगिल पर कब्जा कर लिया। जहां से भारत प्रशासित कश्मीर में श्रीनगर एवं लेह को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दिखता है। इस राजमार्ग को बंद कर देने से कश्मीर घाटी एवं लद्दाख का संपर्क कट जाता है। जिसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यह संघर्ष अणु युद्ध की तरफ़ बढ़ता जा रहा था। लेकिन तत्काल अमेरिकी प्रमुख बिल क्लिंटन के हस्तक्षेप से यह रुक गया। पाकिस्तानी सेना एवं त्रासवादियो ने इस इलाके को खाली कर दिया। भारत ने पुनः इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब यहां पूरे

साल भारतीय सेना की उपस्थिति रहती है (विकिपीडिया)।

२.१.१२ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, २०१९

५ अगस्त, २०१९ के दिन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाली धारा ३७० समाप्त करने के लिए "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, २०१९" भारत की संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम के मुताबिक जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया: (१) जम्मू एवं कश्मीर, (२) लद्दाख। यह अधिनियम भारत के पहले गृह मंत्री स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि ३१ अक्तूबर, २०१९ से लागू कर दिया गया । किसी भी तरह का लोग प्रतिरोध न हो इसके लिए केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में ३५,००० अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया। राज्य को बंद कर दिया गया। इंटरनेट सहित अन्य संचार सेवाएं रोक दी गई। समग्र राज्य में धारा १४४ लागू कर दी गई। कई नेताओं समेत तकरीबन ४००० से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के बंधनों में आहिस्ता आहिस्ता ढील दी गई (विकिपीडिया)।

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य से धारा ३७० का निरसन एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ को पारित किया तो इसकी सबसे ज्यादा आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी राजनयिक, व्यापारिक इत्यादि संबंध तोड़ दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि, इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद के लिए एक पार्टी के रूप में पाकिस्तान अवैध कदमों का मुकाबला करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का प्रयोग करेगा। इसने नीरसन को "एकतरफा कदम" कहा और कहा की, इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। अगस्त, २०१९ पर ६ सेना कमांडरों की एक बैठक के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा था कि, पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों के समर्थन हेतु किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए अगस्त में पाकिस्तान संसद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इसे "गैरकानूनी, एक तरफा, लापरवाह और जबरजस्त प्रयास" के रूप में भारत अधिकृत कश्मीर की विवादित स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया, जैसा कि UNSC के प्रस्तावो में निहित था। ७ अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में भारत के साथ पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों को कम करने का निर्णय लिया गया। भारत से पाकिस्तान के राजदूत को वापस बुला लिया गया और पाकिस्तान से भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया गया। अगले दिन पाकिस्तान के रेलवे मंत्री शेख रशीद अहमद ने "समझौता एक्सप्रेस" ट्रेन सेवा और "थार एक्सप्रेस" को निलंबित कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के साथ सभी सांस्कृतिक आदान-प्रदान, भारतीय चलचित्र और पाकिस्तान के अंदर नाटक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। यहां एक अच्छी बात यह थी कि, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस परिषद में घोषणा की कि, पाकिस्तान तनाव के बावजूद सिखों के लिए "करतारपुर कॉरिडोर" खोलने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और कहा कि हम बाबा गुरु नानक की ५५० वी जन्मतिथि के लिए अपने सिख भाइयों और बहनों का स्वागत करने के लिए तैयार है। बाद में इस नए कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही इसे सिख धर्मीओ के लिए खोल दिया गया। ९ अगस्त, २०१९ को पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को निलंबित कर दिया और भारत से सभी निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ११ अगस्त, २०१९ को प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि,

कश्मीर पर वैश्विक निष्क्रियता हिटलर को खुश करने के समान होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि, भारत "जातीय सफाई" के माध्यम से मुस्लिम बहुसंख्यक कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि, क्या दुनिया हिटलर के लिए भी वैसा ही दिखेगी और अभी करेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार १३ अगस्त, २०१९ को एक बयान जारी किया कि, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था। जिसमें भारत के अवैध कार्यों पर चर्चा करने के लिए परिषद की एक आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था, जो कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करता है। विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच पत्र के प्रचलन के लिए भी कहा। २० अगस्त, २०१९ को पाकिस्तान ने घोषणा की कि, वह इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएगा, यह कहते हुए की, उसका ध्यान भारत द्वारा कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर केंद्रित होगा (विकीपीडिया)।

२.१.१३ पंजाब समस्या

भारत द्वारा बांग्लादेश के लिए १९७१ में किए गए युद्ध का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पंजाब में १९७० एवं १९८० में चली खालीस्तान मुहिम को मदद की थी। इस काम को अंजाम दिया था पाकिस्तानी जासूसी संस्था आईएसआई ने। उसने खालिस्तान तरफी "इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन" जैसी संस्थाओं को मदद पहुंचाई थी (विकिपीडिया)।

३.२ हिंदू-मुस्लिम धार्मिक दंगे, विभाजन, युद्ध और त्रासवाद का भारत और पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव

ब्रिटिश भारत शासन काल में अंग्रेजों द्वारा "फूट डालो और राज करो" की नीति, भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई तकरार, हिंदुओं एवं मुस्लिमों के बीच हुए धार्मिक दंगा फसाद, लोगों का स्थानांतरण, शरणार्थियों की समस्या, १९४७ का पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध, १९६५ में हुआ दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध, १९७१ में हुआ तीसरा भारत-पाकिस्तान युद्ध, १९८९ में जम्मू और कश्मीर में हुआ विद्रोह एवं त्रासवाद का उद्भव, १९९९ में हुआ चौथा भारत-पाकिस्तान का कारगिल युद्ध, पंजाब समस्या, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, २०१९ इत्यादि कई घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान की सरकार एवं जनता पर गहरा एवं नियमित नकारात्मक प्रभाव है। दोनों राष्ट्रों की जनता और सरकार राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, वैचारिक, रमत गमत, उद्योग एवं व्यवसाय, साहित्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जनसंचार माध्यम, शिक्षा, धर्म, सहयोग इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में बटी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता काल से चली आ रही विभाजन कारी विचारधारा का दर्शन होता है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। प्रतिक्षण दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले रहते हैं। मौका मिलने पर दोनों हर तरह का हमला करने की फिराक में रहते हैं। दोनों एक दूसरे को शंकाशील, अविश्वसनीय, विनाशकारी, एवं हेय दृष्टि से देखते हैं। दोनों के बीच दिन-ब-दिन और दूरियां बढ़ती रहती है। धार्मिक दृष्टि से दोनों राष्ट्रों की हिंदू और मुस्लिम जनता एक दूसरे की खून की प्यासी बन बैठी है। धर्म के नाम पर किसी भी वक्त कुछ भी बुरा हो सकता है। धार्मिक दूरियां इतनी बढ़ी हुई है कि उन्हें युगो तक कोई नहीं पाट सकेगा। दोनों राष्ट्र एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। दोनों में निरंतर ठंडा युद्ध चलता रहता है।

३.३ विभाजनकारी विचारधारा का भारत और पाकिस्तान के जनसंचार माध्यमों पर प्रभाव

भारत और पाकिस्तान के दरमियान प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता काल से चली आ रही विभाजन कारी विचारधारा का प्रतिबिंब दोनों राष्ट्रों के जनसंचार माध्यमों में भी निरंतर प्रतिबिंबित होता रहता है एवं दिन-ब-दिन और

दृढ़ होता जा रहा है। दोनों राष्ट्रों के माध्यम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। वह दोनों राष्ट्रों की तरह आपसी दुश्मन बने बैठे हुए हैं। आपस में एक दूसरे के राष्ट्र को कोसते रहते हैं, टीका-टिप्पणी में लगे रहते हैं। अपने अपने राष्ट्रों की तरफदारी में लगे रहते है। एक दूसरे के राष्ट्र को नीचा दिखाने में एवं बुराई करने में लगे रहते हैं। अपने अपने राष्ट्रों का स्वार्थ ढूंढते नजर आते हैं। अपने अपने राष्ट्र के विचारों का समर्थन करते रहते हैं। इन सभी कार्यों में नीतिमत्ता और निर्पेक्षता का ज्यादातर अभाव दिखता है। दोनों राष्ट्रों के जनसंचार माध्यम ज्यादातर अपने अपने राष्ट्र के विदेश मंत्रालय की तरह काम करते रहते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि, हम पत्रकारिता करते हैं सरकार नहीं चलाते हैं, न विदेश नीति करते हैं। दोनों राष्ट्रों के माध्यमों का कामकाज और उन में प्रसिद्ध होने वाली सामग्री से ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्र हित, राष्ट्र सुरक्षा, धर्म सुरक्षा, लगुमतिओ की सुरक्षा, विदेश नीति, दोनों राष्ट्रों के साझा मसाईल इत्यादि उनकी जिम्मेदारी है। वह इन्हीं सामग्री से भरे पड़े दिखाई देते हैं। दोनों राष्ट्रों के जनसंचार माध्यम मौका मिलते ही माध्यमों का नीतिशास्त्र भूलकर एक दूसरे के राष्ट्र में बनती रहती राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक, सीमा विवाद, त्रासवाद, सेना की गतिविधियां, जम्मू-कश्मीर विवाद, सिंध और पंजाब के बीच नदियों के पानी का बटवारा और बांधों के निर्माण का विवाद, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध, जासूसी, एक दूसरे के खिलाफ साजिशे इत्यादि घटनाओं पर टूट पड़ते हैं, आलोचना करने में लग जाते हैं और कई बार मर्यादाएँ भूल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि, दोनों राष्ट्रों के माध्यम एक दूसरे के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते हैं। वह एक दूजे के राष्ट्र में बनती रहती अच्छी घटनाओं की सराहना करते रहते हैं, एक दूजे को ग्रहण करने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन इसका अनुपात बहुत कम रहता है।

४.४ पाकिस्तानी उर्दू अखबारों में विभाजनकारी विचारधारा का प्रभाव

विभाजनकारी विचारधारा के बारे में ऊपर जो देखा वह पाकिस्तान के जनसंचार माध्यमों में स्वतंत्रता काल से आज तक संपूर्ण प्रतिबिंबित होता रहता है और दिन-ब-दिन ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इस संदर्भ में यहां पाकिस्तानी उर्दू अखबारों का विश्लेषण दिया गया है। इस विश्लेषण में भारत में होने वाली उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसका संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ है या फिर भारत में होने वाली घटनाओं का की जिसमें पाकिस्तानी उर्दू माध्यम रुचि रखते हैं और उसमें विभाजनकारी विचार देखने को मिलते हैं।

२०१४ में भारत में हुए आम चुनाव में "राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा" ने भारी जीत हासिल की थी। उसकी जोरदार चर्चा पाकिस्तान के उर्दू माध्यमों में हुई थी। पाकिस्तान के सभी बड़े अखबारों ने भारत के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को अपनी पहली खबर बनाया था और पहले पन्ने पर उस तस्वीर को भी जगह दी थी जिसमें नरेंद्र मोदी जीत के बाद अपनी मां का आशीर्वाद ले रहे थे। पाकिस्तान के बहू संस्करणीय अखबार "जंग" ने सुर्खी लगाई थी कि "भारत के युवाओं में बीजेपी कामयाब, कांग्रेस का सफाया।" "नवा ए वक्त" ने बॉलीवुड के कई चेहरों की तस्वीरें दी थी, जिसमें जीतने वालों में विनोद खन्ना, बप्पी लाहरी, हेमा मालिनी जैसे नाम शामिल थे, तो हारने वालों में जयाप्रदा, राज बब्बर और राखी सावंत। दैनिक "दुनिया" ने एक पूरा पन्ना नरेंद्र मोदी को समर्पित किया था और उनकी बड़ी सी तस्वीर के साथ बड़े-बड़े से लेख में नरेंद्र मोदी के जीवन और उपलब्धियों के बखान किए गए थे। जिसमें लिखा था कि, देखना यह है कि पाकिस्तान को लेकर वह किस तरह की नीतियां अपनाने है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की बहाली पर "जंग" ने अपने

संपादकीय में खुशी जताई थी और लिखा था कि, दोनों देशों के बीच २०१५ से २०१३ के बीच होने वाली ६ क्रिकेट श्रृंखलाओं से ४ की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और दो सीरीज भारत में होगी। “नवा ए वक्त” ने भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर मसले पर चीन ने मध्यस्थता करने की पेशकश की थी उसके ऊपर संपादकीय लिखा था, जिसमें भारत के दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त को ईमानदार बताया था और उसे प्रभावी भूमिका अदा करने की सलाह दी थी, जो भारत के लिए ना गुजर है। अखबार ने संपादकीय में लिखा था कि, यकीनन चीन की ईमानदारी पर किसी संदेह की गुंजाइश नहीं, लेकिन जाहिर है कि भारत उसकी मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा देगा, इसलिए मौजूदा हालात में जरूरत इस बात की है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के “वीटो पावर” वाले सदस्य के रूप में कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार हल के लिए प्रभावी भूमिका अदा करें (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

२०१४ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए थे। इस दौरे के नफा नुकसान का आकलन पाकिस्तानी उर्दू माध्यमों ने अपने हिसाब से किया था। रोजनामा “दुनिया” ने प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा वक्त नवाज शरीफ को देना, दोनों प्रधानमंत्रियों और शीर्ष प्रतिनिधिमंडल की लंबी बातचीत, उसका नतीजा इत्यादि बातों पर अपनी राय जाहिर की थी। रोजनामा “दुनिया” ने लिखा था कि, प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यस्तता और हजारों मेहमानों के बीच सबसे ज्यादा वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिया। दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल की ५० मिनट बात हुई जिसमें वह १५ मिनट भी शामिल है जिसमें दोनों प्रधानमंत्रियों ने अकेले बात की। लेकिन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को इस मुलाकात से सिवाय चार्जशीट के कुछ हासिल नहीं हुआ। बल्कि जिसे चार्जशीट कहा जा रहा है, वे वही बातें है जो भारत दोहराता रहता है। मसलन पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों को रोके, २००८ के मुंबई हमले से जुड़े मुकदमे की तेजी से सुनवाई हो, पाकिस्तान मुंबई हमलों की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें वगैरह वगैरह। इस विषय पर रोजनामा “पाकिस्तान” ने अपने विचार रखे थे, जो कि रोजनामा “दुनिया” से मेल खाते थे। रोजनामा “दुनिया” ने भी यही कहा था कि, यदि भारत २००८ के मुंबई हमले पर अटका रहेगा तो पाकिस्तान का जवाब भी पहले जैसा ही होगा। अखबार ने लिखा था कि, इसका साफ मतलब है कि मामला वही रहेगा जहां है, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी और जिन खाली नेक ख्वाहिशों का इजहार किया जा रहा है, उन पर अमल नहीं हो सकेगा। “नवा ए वक्त” ने इस मुलाकात को पाकिस्तान के नजरिए से निष्फल बताया था। अखबार ने इस घटना पर अपने विचार रखते हुए कहा था कि, यह मुलाकात भारत के नजरिए से तो सकारात्मक हो सकती है लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से हरगिज़ नहीं। फिर न जाने क्यों विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज इसे उम्मीद से ज्यादा कामयाब बता रहे हैं। दोनों देशों की इस बातचीत में कश्मीर को एजेंडे पर न रखने के लिए भी अखबार ने पाकिस्तान सरकार की खिंचाई की थी (बीबीसी हिंदी, २०१४)

२०१४ से पाकिस्तानी उर्दू माध्यमों में भारतीय साजिशों के आरोपों की चर्चा बहुत हुई थी। २०१४ में कराची हवाई अड्डे पर त्रासवादी हमला हुआ था। इस हमले के बाद “जंग” अखबार ने लिखा था कि, भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ा रही है। अखबार ने यह भी लिखा था कि, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार ६० गुट है जो इस वक्त तोड़फोड़ की कार्रवाई में लगे हैं। अखबार के मुताबिक, ऐसे में सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है कि तालिबान से शांति वार्ता खत्म कर ऑपरेशन की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन अखबार की

हिदायत है कि, जो भी कदम उठाए जाए उसमें सियासी और सैन्य नेतृत्व एक साथ हो (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

२०१४ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक खत लिखा था। इसको लेकर पाकिस्तानी उर्दू मीडिया ने नवाज शरीफ की कही आलोचना तो कही तारीफ की थी। “नवा ए वक्त” ने लिखा था कि, भारत के खुद करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपने करोड़ों गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए मोदी से मदद मांग रहे हैं। अखबार ने आगे लिखा था कि, कराची में हुए हालिया हमले में जब भारत के हथियारों के इस्तेमाल होने के ठोस सबूत मिले हैं तो फिर भारत को यह शांति और प्रेम वाला खत क्यों लिखा गया? इस घटना पर “जंग” अखबार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए लिखा था कि, कराची एयरपोर्ट पर हुए हमले में भारतीय हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों की जांच से पहले किसी पर आरोप न लगाया जाए। रोजनामा “दुनिया” ने इस प्रयास की सराहना की थी। उसने लिखा था कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेकर जिस काम का आगाज किया था यह ताजा पत्र उस काम को आगे बढ़ाने की एक गंभीर कोशिश है। उम्मीद है कि, मोदी सरकार इस हकीकत को समझने की कोशिश करेगी कि दोनों देशों के अच्छे संबंध दक्षिण एशिया के डेढ़ अरब लोगों के लिए कितना महत्व रखते हैं (बीबीसी हिंदी, २०१४)

भारत सरकार द्वारा असुरक्षा का कारण बताकर जून, २०१४ में ३०० भारतीय सिखों को एक मेले में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान न जाने देने पर दैनिक “एक्सप्रेस” ने एतराज जताया था। दैनिक ने इसे भारत द्वारा विश्व में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश बताया था और भविष्य में ऐसी प्रवृत्तियों से पाकिस्तान को सावधान रहने के लिए कहा था। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था कि, भारतीय सीखो को लेने पाकिस्तान से स्पेशल ट्रेन गई, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने यह कहते हुए उन्हें नहीं आने दिया कि, पाकिस्तान असुरक्षित है। अखबार ने कहा था कि, पाकिस्तान में सिख यात्रियों के लिए कभी कोई समस्या नहीं रही, इसलिए भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कदम उठाया। वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि, पाकिस्तान एक असुरक्षित देश है (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

भारत के २०१४ के बजट में रक्षा के लिए १२ फ़ीसदी की वृद्धि एवं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की योजना की पाकिस्तानी उर्दू माध्यमों ने जमकर सख्त आलोचना की थी। इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर पड़ने वाले प्रभाव की एवं भारत की पाकिस्तान के प्रति नियत की बहुत चर्चा हुई थी। “नवा ए वक्त” भारत के रक्षा बजट में की गई १२ प्रतिशत बढ़ोतरी एवं कश्मीर में पुनः कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए बजट में ५ अरब रुपए देने के प्रस्ताव पर लिखा था कि, २२ खरब ९० अरब रुपए की राशि भूख और बदहाली के शिकार देश की सुरक्षा के लिए रखी गई है। अख़बार के अनुसार यही नहीं, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की योजना से वहां चिंता की लहर दौड़ गई है। अखबार का कहना था कि, पाकिस्तान सरकार तो भारत सरकार से रिश्तो में बेहतरी की उम्मीद लगाकर बैठी है, जबकि भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर पाकिस्तान की संप्रभुता खत्म करने के मंसूबे बना रहा है। भारत के रक्षा खर्च में इजाफे पर अखबार ने लिखा था कि, भारत को अपना जंगी जुनून छोड़कर गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने पर जोर देना चाहिए (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

२०१४ में “ब्रिक्स” सम्मेलन में “ब्रिक्स” देशों ने अपना बैंक बनाने की घोषणा की थी। इस विषय पर “जंग” ने संपादकीय लिखा

था। जिसमें भारत के चलते यह बैंक पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? इस बात पर शंका जाहिर की गई थी। अखबार ने लिखा था कि, इस बैंक में पाकिस्तान का दोस्त चीन अहम भागीदार है लेकिन उसके साथ भारत भी है, जिसका रवैया पाकिस्तान को लेकर जगजाहिर है। ऐसे में देखना होगा कि, यह बैंक पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच २०१४ में भारी गोलाबारी हुई थी। यह घटना पाकिस्तान के उर्दू माध्यमों में सुर्खियों में रही थी। इस घटना की उर्दू माध्यमों ने जमकर टीका की थी और शंका जताई थी कि, यह सरकार ताकत के जरिए समूचे कश्मीर को अपने में सम्मिलित करना चाहता था। इस घटना के संदर्भ में "नवा ए वक्त" ने अपने संपादकीय में लिखा था कि, भारत सरकार सीमा पर तनाव बढ़ा रही है और घुसपैठ के आरोप पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं। इससे लगता है कि, वह अपने कार्यकाल में कश्मीर मुद्दे को ताकत के दम पर हल करना चाहती है (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की पाकिस्तान में २०१४ में बैठक होने वाली थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तानी माध्यमों ने इसे माहौल खराब करने की कोशिश बताया था। पाकिस्तान की तरफ से परोक्ष युद्ध चलाए जाने के भारत के प्रधानमंत्री के आरोपों पर "नवा ए वक्त" के संपादकीय अनुसार , भारत को आरोप लगाने की बजाय कश्मीरियों को जनमत संग्रह का हक देना चाहिए। अखबार का कहना था कि, भारतीय सेना ने पूरी कश्मीर घाटी को छावनी में तबदील कर लोगों को उनके घरों में कैद कर रखा है और ऐसे में अगर कश्मीरी अपने अधिकारों के लिए कोशिश भी करते हैं तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है, जबकि वह तो खुद दहशतगर्दी के शिकार है। इस घटना पर अपनी राय इजहार करते हुए "जंग" अखबार ने लिखा था कि, विदेश सचिवों की इस्लामाबाद में बैठक से पहले माहौल को खराब करने की कोशिश है (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

उपरोक्त विदेश सचिवों की बैठक को भारत ने रद्द कर दिया था। जिसकी पाकिस्तानी उर्दू माध्यमों ने खूब टीका-टिप्पणी की थी। "जंग" ने दोनों देशों की विदेश सचिव स्तरीय बातचीत रद करने को भारत का नकारात्मक रवैया करार दिया था। अखबार का कहना था कि, हुर्रियत के नेताओं से सलाह मशविरा दशकों से होता रहा है। इसे मुद्दा बनाकर बातचीत करना और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी फैलाने के आरोप लगाना अफसोसनाक है। इस घटना के संदर्भ में "नवा ए वक्त" ने लिखा था कि, दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मिलकर लौटे हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की श्रीनगर में गिरफ्तारी पाकिस्तानी सरकार के लिए चिंता का विषय है। अखबार का कहना था कि, पाकिस्तान को भारत सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और बेहतर होगा कि नवाज शरीफ सरकार साफ कर दे कि दोनों देशों के रिश्ते और व्यापार तभी आगे बढ़ेंगे जब कश्मीर मुद्दे के हल के कदम उठाए जाएंगे (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

भारत और पाकिस्तान के बीच २०१४ में जम्मू-कश्मीर की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी हुई थी। जिसमें कई लोग हताहत हुए थे। इस घटना पर पाकिस्तान के उर्दू अखबारो ने भारत को मानो ललकारा था। भारत को पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान न लेने को, चोर को कोतवाल को न मारने की एवं भारी तबाही से बचने की नसीहत दे डाली थी। "इंसाफ" रोजनामा का संपादकीय था कि, "दुश्मनों के खिलाफ एकता और सहमति की जरूरत।" अखबार ने एक तरफ भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी में १३ पाकिस्तानियों के मारे जाने की

बात की थी तो कबायली इलाकों में ईद की छुट्टियों के दौरान अमेरिकी ड्रोन हमलों में १८ लोगों की मौत का मुद्दा भी उठाया था। अखबार ने आगे लिखा था कि, अमेरिका और भारत, पाकिस्तान की जंग की क्षमताओं को परखना चाहते हैं। ऐसे में अगर उसके खिलाफ युद्ध शुरू किया गया तो परमाणु शक्ति के इस्तेमाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी घटना पर "नवा ए वक्त" ने जो लिखा था उसका सा उसका सारांश यही था कि, भारत सरकार पाकिस्तान पर दहाड़ रही हैं लेकिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पूरी तरह खामोश है। अखबार ने जहां भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी फौज की तारीफ की थी वहीं सरकार को भारत से हर तरह के संपर्क छोड़ने की नसीहत दी थी। रोजनामा "वक्त" ने पाकिस्तान पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के भारत के आरोपों पर लिखा था कि, "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।" अखबार का कहना था कि, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है कि वह भारत को रोके वरना भारत को ही इसके अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। "औसाफ" ने अपने संपादकीय में खुले तौर पर भारत को युद्ध की चेतावनी दे डाली थी। वही दैनिक "उम्मत" का संपादकीय था, "भारत भारी तबाही को दावत न दे" (बीबीसी हिंदी, २०१४)

२०१४ में नेपाल में "सार्क सम्मेलन" हुआ था। सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को एक दूसरे से दूर रखा था। इसका प्रमुख कारण दोनों राष्ट्रों के बीच विदेश स्तर की बातचीत को भारत द्वारा रद्द करना था। इस घटना की पुरजोर चर्चा पाकिस्तान के उर्दू माध्यमों ने की थी। माध्यमों ने नवाज शरीफ की पीठ थपथपाई थी, लेकिन हैरत तब हुई जब दोनों राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों के हस्तधुनन की तस्वीर सामने आई। "सार्क" की सफलता-निष्फल की भी खूब चर्चा हुई थी। "ओसाफ़" ने लिखा था कि, "सार्क कॉन्फ्रेंस" में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ न तो भारत की तरफ से राष्ट्राध्यक्षो या सरकार प्रमुखों के लिए मुहैया कराई गई बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे और न उन्होंने भाषण के लिए जाते समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी से दुआ सलाम की। अखबार के अनुसार, यह सब देखकर पाकिस्तान के ज्यादातर लोग बड़े खुश हुए, लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की हाथ मिलाती हुई तस्वीर सामने आई। अखबार को एतराज था कि, शरीफ ने इस मुलाकात में विदेश सचिव स्तर की वार्ता टालने पर तो शिकवा किया पर यह नहीं कहा था कि, भारत नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी क्यों नहीं रोकता? वहीं "जंग" ने "सार्क" को मजबूत और फायदेमंद बनाने पर जोर दिया था। अखबार ने लिखा था कि, "सार्क कॉन्फ्रेंस" अपने ८ सदस्य देशों के लगभग २ अरब लोगों की शांति, विकास और तरक्की से जुड़ी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी, लेकिन रीजनल इलेक्ट्रिक ग्रिड के जरिए बिजली समझौते पर हस्ताक्षर करके यह सम्मेलन पूरी तरह विफलता के दाग से बच गया है। अखबार ने "सार्क" की मजबूती के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों के हल की जरूरत पर जोर दिया था। उधर "नवा ए वक्त" ने सलाह दी थी कि, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत को लेकर पहले जैसी खुशफहमी में न रहे (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

२०१४ में रूस के प्रमुख व्लादीमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे। उस वक्त दोनों देशों के बीच परमाणु रिएक्टर निर्माण, लड़ाकू और परिवहन विमानों की साजा तैयारी, सैन्य प्रशिक्षण, तेल की तलाश और आपूर्ति जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। इसकी जोरदार तीखी, कड़क एवं आलोचनात्मक गूंज पाकिस्तान के उर्दू माध्यमों में सुनाई दी थी। उर्दू माध्यमों ने इस दौरे को पाकिस्तान के लिए कितना जोख्मी और भारत के लिए कितना फायदेमंद रहा था एवं पाकिस्तान को रूस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? उसकी चर्चा की थी। "औसाफ" ने लिखा

था कि, जो विश्लेषक मान रहे थे कि अमरिका की तरफ भारत के झुकाव की वजह से रूस उससे नाराज है और इस लिए पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करना चाहता है, उन्हें आंख खोलकर देखना चाहिए कि भारत और रूस के बीच कितने बड़े और अहम समझौते हुए हैं। अखबार के मुताबिक, दूसरी तरफ हम है कि अपने सबसे अहम दोस्त चीन के राष्ट्रपति का दौरा स्थगित करा कर कोई अफसोस भी नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान करा बैठे हैं। “जंग” ने लिखा था कि, मोदी और पुतिन के बीच समझौते के तहत रूस अगले २० साल में भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने के अलावा लड़ाकू और परिवहन विमानों की साजा तैयारी, सैन्य प्रशिक्षण, तेल की तलाश और आपूर्ति में सहयोग करेगा। लेकिन अखबार ने उम्मीद करते हुए लिखा था कि, बदलती दुनिया में रूस और भारत का सहयोग, साजो-सामान की तैयारियां के अलावा दक्षिण एशिया को भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं से निपटने में मददगार होगा। दैनिक “एक्सप्रेस” ने इस घटना पर लिखा था कि, अमेरिका के साथ भारत का परमाणु समझोता तो मनमोहन सरकार के दौरान ही हो गया था, लेकिन अब इस क्षेत्र में रूस भी खुले दिल से भारत की मदद कर रहा है। अख़बार के अनुसार, इससे भारत की युद्ध क्षमता बढ़ेगी और पाकिस्तान को लेकर उसके रवैये में और घमंड आएगा। “नवा ए वक्त” ने भी अमेरिकी और रूस के साथ भारत के समझौतों को हथियारों के प्रति उसके जुनून का नाम दिया था और इसे पाकिस्तान की संप्रभुता को खतरा बताया था। अखबार ने लिखा था कि, इस जुनून को देखते हुए भारत से यह उम्मीद बेमानी है कि वह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से कोई बात करेगा। इसलिए जरूरी है कि, कश्मीर मुद्दे पर भारत के दोहरे रवैए से दुनिया को अवगत कराएं (बीबीसी हिंदी, २०१४)।

पाकिस्तान के पेशावर में २०१४ में एक शाला पर त्रासवादी संगठन तालिबान ने हमला करके १४० लोगों को मार दिया था। मृतकों में ज्यादातर बच्चे थे। इस घटना से पाकिस्तान और पूरा विश्व हिल गया था। त्रासवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी थी। जिसके चलते पाकिस्तान ने फांसी पर जो लंबे समय से प्रतिबंध लगा रखा था उसे तत्काल प्रभाव से उठा लिया गया। इस पर यूरोपीय संघ आपत्ती जताई थी। पाकिस्तानी उर्दू माध्यमों ने इस पर कड़ा एतराज जताया था और साथ में भारत को भी घसीटा था। इस घटना पर “औसाफ” ने लिखा था कि, दहशतगर्द हमारे बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं और यूरोपीय संघ अब भी पाकिस्तान में मौत की सजा का विरोध कर रहा है। अखबार के मुताबिक भारत सजा-ए-मौत दे तो यूरोपीय संघ को कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब फांसीया दे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में सजा-ए-मौत पर यूरोपीय संघ को तकलीफ है (बीबीसी हिंदी, २०१४)

जनवरी २०१५ में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे पर आए थे। ओबामा के भारत दौरे पर पाकिस्तानी उर्दू माध्यम चिढ़ गए थे। इस दौरे की पाकिस्तानी उर्दू माध्यमों में लंबे वक्त चर्चा चली थी। उन्होंने अमरिका का भारत प्रति झुकाव, पाकिस्तान की कमजोर विदेश नीति, अमरिका की बदलती प्राथमिकताएं, अमरिका की मंशा, भारत और अमरिका के बीच हुए कई समझौते एवं उनका पाकिस्तान पर होने वाला प्रभाव, भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता को अमरीका का समर्थन, पाकिस्तान का सच्चा दोस्त चीन जैसे मुद्दों पर खूब चर्चा एवं आलोचना की थी। दैनिक “एक्सप्रेस” ने लिखा था कि, अमरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे से साफ हो गया है कि अमेरिका आने वाले समय में इस क्षेत्र में किस तरह की नीति को लागू करना चाहता है। अखबार ने लिखा था कि, भारत की तरफ अमरिका का झुकाव इतना बढ़

गया है कि वह उसे सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाने का समर्थन तक कर रहा है। अखबार के मुताबिक, अमरिका अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान कभी भी चीन के खिलाफ अमरिका का साथ नहीं देगा, इसलिए उसने भारत को चीन का रास्ता रोकने का जरिया बनाया है। "नवा ए वक्त" ने इस दौरे पर लिखा था कि, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब अमेरिका गए तो राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें चंद मिनट की मुलाकात का भी वक्त नहीं दिया और भारत आए तो अपने अहम सहयोगी पाकिस्तान की तरफ कमर करके वापस लौट गए। अखबार ने लिखा था कि, इससे भारत की कामयाब और हमारी कमजोर विदेश नीति का पता चलता है। "औसाफ" ने बराक ओबामा के भारत दौरे पर लिखा था कि, भारत के प्रधानमंत्री के हाथों बनी चाय पीने के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने जिस तरह दिलदारियां दिखाई है उससे पता चलता है कि वाशिंगटन की प्राथमिकताए बदल गई है, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में बदलती रही है। अखबारों ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्य की दावेदारी पर भी सवाल उठाया था और भारत और अमेरिका के बीच नए रक्षा समझौतों को पूरे क्षेत्र के लिए एक नया खतरा भी बताया था। दैनिक "वक्त" ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के चीन दौरे के हवाले से लिखा था कि, पाकिस्तान-चीन दोस्ती हर तरह के संदेह से ऊपर है, अब बात चाहे १९६५ में पाक-भारत युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने की हो या फिर सैन्य साजो-सामान की आपूर्ति या फिर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग। अखबार ने लिखा था कि, इस दोस्ती की गहराई को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में अकेला नहीं है (बीबीसी हिंदी, २०१५)।

२०१५ में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे अमरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी माध्यम क्रोधित हो गए थे। भारत को इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अपने "पाकिस्तान दिवस" पर होने वाली सैन्य परेड में भारत के दुश्मन चीन के राष्ट्रपति शीन जिनपिंग को मुख्य अतिथि बनाया था। पाकिस्तानी उर्दू माध्यमों ने इस घटना को खूब उछाला था और पाकिस्तान की विदेश नीति पर खासतौर पर चर्चा की थी एवं इसको भारत-अमरिकी गठजोड़ के खिलाफ़ ठोस संदेश के रूप में प्रस्तुत किया था। इस घटना पर अपना विचार रखते हुए "नवा ए वक्त" ने लिखा था कि, यह दुनिया को अमरीका-भारत गठजोड़ के खिलाफ ठोस पैगाम है। अखबार ने लिखा था कि, भारत के गणतंत्र दिवस पर अमरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का दिल्ली आना और दोनों देशों के बीच परमाणु रक्षा सहयोग के समझौते होना पाकिस्तान के लिए एक खुली चुनौती थी। अखबार के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के हित साजा है और इसलिए उनका दुश्मन भी साझा है, ऐसे में चीन ने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान के हितों से ही चीन के हित भी जुड़े हैं। "एक्सप्रेस" ने लिखा था कि, ओबामा ने अपने भारत दौरे में जिस तरह भारत पर मेहरबानियां की बारिश की और उसे सुपर पावर बनाने के समझौते किए, वह पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। "औसाफ" ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक इंटरव्यू का जिक्र किया था जिसमें वह कहते हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत जाने से पहले उन्हें भरोसे में लिया था। लेकिन अखबार की टिप्पणी थी कि, यह ऐसा बदकिस्मत दौर है जब पाकिस्तान की कोई विदेश नीति नहीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग-थलग किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि, एक मजबूत रक्षा विदेश नीति के अलावा प्रभावी कानून बनाए जाए। वही "जंग" ने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरिकी सैन्य मदद छह गुना करने कि राष्ट्रपति ओबामा की सिफारिश पर संपादकीय लिखा था। उसके मुताबिक इससे साफ होता है कि, अमेरिका ने दहशतगर्दी और चरमपंथ से निपटने के

पाकिस्तान के प्रयासों को मान्यता दी है, लेकिन पाकिस्तान ने इस लड़ाई में जितना जानो-माल का नुकसान झेला है और झेल रहा है, उसके मुकाबले यह ज्यादा नहीं है। दैनिक "दुनिया" ने अपने संपादकीय में कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए लिखा था कि, पाकिस्तान कश्मीरियों के संघर्ष का समर्थन चंद वर्ग हजार किलोमीटर के इलाके की खातिर नहीं करता और न ही वह भारत की तरह विस्तारवादी रवैया रखता है, बल्कि वह तो अपने वजूद के लिए लड़ रहे सवा करोड़ कश्मीरियों के संघर्ष के साथ है। अखबार के मुताबिक, कश्मीरियों का समर्थन करने कि पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की है। लेकिन फिर भी वो अपने उस संकल्प से नहीं डिगा है जो उसने १४ अगस्त, १९४७ को लिया था (बीबीसी हिंदी, २०१५)।

ऐसा नहीं है कि, पाकिस्तान के जनसंचार माध्यम हर वक़्त भारत को कोसते रहते हैं। वह भारत में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं पर अच्छी चर्चा भी करते हैं और उनसे पाकिस्तान को प्रेरणा लेने की हिदायत भी देते हैं। २०१५ में दिल्ली राज्य में , "आम आदमी पार्टी" की जीत और उसके सियासी निहितार्थो पर पाकिस्तान के उर्दू माध्यमों ने खूब चर्चा की थी और पाकिस्तान के सियासतदानों को इससे कुछ सीखने को कहा था। इस विषय पर "जंग" ने लिखा था कि, सूचना और जानकारी के आधुनिक माध्यमों के कारण लोगों में बहुत जागरूकता आई है, अब ऐसे नेता उनकी पसंद बन रहे हैं जो उन्हीं के बीच से हो, उनके जैसी जिंदगी जीते हो, उनके दुख-दर्द और समस्याओं को जानते हो और उन्हें हल करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने को तैयार हो। अखबार के मुताबिक, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के पारंपारिक सियासतदानों को इस स्थिति से सबक सीखना होगा। "एक्सप्रेस" लिखता है की, भारत में चुनाव न सिर्फ पारदर्शी होते हैं बल्कि हर पार्टी अपनी विरोधी पार्टी की जीत को खुले दिल से स्वीकार करती है, तभी तो शुरुआती नतीजों के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को फोन पर बधाई दी। अखबार के मुताबिक, दिल्ली के नतीजे यह भी बताते हैं कि, जो सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती उसे लोग बक्शते नहीं है, भले ही उसने लगातार १५ साल तक दिल्ली में शासन क्यों न किया हो। अपने कार्यकर्ताओं को अहंकार न करने की केजरीवाल की हिदायत पर अखबार ने लिखा था कि, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों और राजनेताओं को भी इससे सीख लेनी चाहिए (बीबीसी हिंदी, २०१५)।

पाकिस्तान विश्व क्रिकेट कप की मेचों में लगातार छठी बार भारत से हारा। छठी बार वो २०१५ के क्रिकेट विश्वकप में हारा। इस घटना पर तमाम पाकिस्तानी अखबारों ने अपना गुस्सा और शक जाहिर किया था। पाकिस्तानी माध्यमों का कहना था कि, देश को बहुत निराशा हुई है और उन्हें अफसोस है कि मिसबाह उल हक की टीम भी अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मैच में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। इस घटना के बारे में अखबार "डॉन" ने लिखा था कि, हां! हम सब को थोड़ा विश्वास था कि शायद हम जीत जाए, लेकिन यह रिकॉर्ड ६-० पर ही कायम रहा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार छठी बार भारत ने हमें बुरी तरह हराया है। अखबार ने चेताया था कि, यदि पाकिस्तान इसी तरह हारता रहा तो उसका रिकॉर्ड ब्राजील से भी बदतर हो जाएगा जो पिछले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी से ७-१ से हारा था। "द न्यूज़" अखबार ने कहा था कि, अब पाकिस्तानी फैंस को अगले ४ साल तक पटाखे रखने होंगे, जब तक पाकिस्तान अगले विश्वकप में भारत को न हरा दे। हालांकि अखबार ने यह भी माना था कि, भारत जैसी मजबूत टीम के सामने यह अनपेक्षित नहीं था। वहीं "द नेशन" अखबार ने कहा था कि, रविवार की हारने पाकिस्तानी लोगों को २०११ में वर्ल्ड कप सेमी फाइनल में हुई

दुखद हार की याद दिला दी है (बीबीसी हिंदी, २०१५)।

यहां पाकिस्तानी उर्दू प्रेस के कुछ चुनिंदा, महत्वपूर्ण एवं मुख्य धारा के अखबारों के २०१४-१५ के भारत संबंधी वृत्तांतों (Reports) का उपयोग किया गया है। लेकिन यह प्रवृत्ति पाकिस्तानी उर्दू प्रेस में आम बात है। प्रारंभ में देखा था उसके मुताबिक, भारतीय प्रेस मैं भी यह प्रवृत्ति आम बात है, लेकिन यहां पाकिस्तानी उर्दू अखबारों में भारत के बारे में जो वृत्तांत लेखन (Reporting) होता है उसमें स्वतंत्रता काल से चली आ रही विभाजनकारी विचारधारा के प्रभाव के बारे में विश्लेषण किया जाना था, इसलिए यहां केवल पाकिस्तानी उर्दू अखबारों की चर्चा की गई है।

संदर्भ:

BBC monitoring service. (2015, February 16). भारत से हार पर पाक मीडिया में शोक [Pakistan media mourns over defeat from India]. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/hindi/sport/2015/02/150216_pak_media_ world_cup_india_win_mg

Kashmir conflict. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved January 18, 2020 from http:// en.m.wikipedia.org/wiki/kashmir_conflict

Khalistan movement. (n.d.). In wikipedia. Retrieved January 18, 2020 form http://en.m.wikipedia.org/wiki/khalistan_movement

Kumar, A. (2014, June 1). भारत से शरीफ को क्या मिला, सिर्फ चार्ज शीट [What did Sharif get from India, only the charge sheet]. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/hindi/international/ 2014/ 06/140531_ urdu_press_review_aa

Kumar, A. (2014, June 15). पाक मीडिया: कराची हमले में भारतीय हथियारों पर बहस [Pak Media: Debate on Indian weapons in Karachi attack] Retrieved from http://www.bbc.co.uk/hindi/India/2014/06/ 140614_urdu_press_review_aa

Kumar, A. (2014, July 13). कश्मीरी पंडितों पर पाक मीडिया की तिरछी नजर [Pak media has a skewed eye on Kashmiri Pandits]. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/ hindi/international/2014/07/ 140712_urdu_press_review_aa

Kumar, A. (2014, July 20). पाकिस्तानी मीडिया में छाए सुब्रमण्यम स्वामी [Subramanian Swami dominated the Pakistani media]. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/hindi/international/2014/07/ 140719_urdu_media_review_aa

Kumar, A. (2014, August 4). चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का डर [Four days of moonlight then fear of dark night]. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/hindi/international/2014/08/140823 _urdu_media_review_aa

Kumar, A. (2014, September 7). ये पाकिस्तान के दोस्त है या दुश्मन [Is this Pakistan's friend or enemy]. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/hindi/India/ 2014/09/ 140906_urdu_press_review_vr

Kumar, A. (2014, September 14). योगी आदित्य नाथ पर मोदी की चुप्पी का मतलब [Modi's silence on Yogi Adityanath means]. Retrieved from

http://www.bbc.co.uk/hindi/international/2014/09/
140913_urdu_press_review_aa

Kumar, A. (2014, October 12). भारत को ललकार से पाकिस्तान के अखबार [Pakistan's newspapers dare India]. Retrieved from http://
www.bbc.co.uk/hindi/international/2014/10/141012_urdu_press_
review_ aa_

Kumar, A. (2014, October 26). पाक मीडिया: मोदी को कब जवाब देंगे शरीफ [Pak Media: When will Sharif reply to Modi]. Retrieved from
http://www.bbc.co.uk/hindi/international/2014/10/
141026_urdu_press_review_aa

Kumar, A. (2014, November 2). भारत की बड़ी भूमिका में पाक अड़ंगा? [Pak obstruction in India's big role?]. Retrieved from
http://www.bbc.co.uk/hindi/international/2014/11/
141101_urdu_press_review_ aa

Kumar, A. (2014, November 14). पाक मीडिया: तस्वीर ने की खुशी काफूर [Pak media: The picture is a delight]. Retrieved from
http://www.bbc.co.uk/2014/11/141129_urdu_press_review_aa

Kumar, A. (2014, December 7). पाक मीडिया: चर्चा में कश्मीर, दलीलें जुदा [Pak media: Kashmir argument separated in discussion]. Retrieved form
http://www.bbc.co.uk/hindi/India/2014/12/141206_urdu_press_
review_vr.

Kumar, A. (2015, March 1). भारत को मुंहतोड़ जवाब देना होगा: पाक मीडिया [India will have to give a befitting reply: Pak media]. Retrieved from
http://www.bbc.co.uk/hindi/India/2015/03/150228_
urdu_press_review_aa

Kumar, A. (2015, March 2). पाक सहयोग ने पाकिस्तान में भी बटोरी सुर्खियां [Pakistan cooperation also gave headlines in Pakistan]. Retrieved from
http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2015/03/150302_
press_on_kashmir_polls_pm

Partition of India. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved January 17, 2020, From
http://en.m.wikipedia.org/wiki/partition_of_India

भारत का विभाजन. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved January 18, 2020, from http://
hi.m.wikipedia.org/wiki/भारत_का_विभाजन